[Shri Krishna Chandra Halder]

defective policy some big re-rollers in the country have been able to obtain exaggerated capacity certificates several times larger than the actual production, thus depriving the genuine and actual users of the re-rollable materials—the small scale rollers—of their due rights and entitlements. In this connection, I would like to inform the government that a technical committee was appointed by the Government of India in 1978 to make overall study of the problems of re-rolling industry in the country in order to revamp, rehabilitate and rationalise this industry. I understand that the said Committee had submitted its report some 7 months ago, but it appears the said report has been sheleved by the bureaucracy and the vested interests.

I urge upon the Minister to lay the report of the Technical Committee in the House and take urgent steps to implement the recommendations of the Committee in order to save the small scale rollers from being ruined.

(ii) Chemical Fertilizer Factory at Phulpur in U.P.

श्री बो० डो० सिंह : (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत फूलपुर स्थित रासायनिक खाद के कारखाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह कारखाना इंडियन फ़ार्मर्ज़ फर्टलाइज़र कोआपरेटिव लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। इस कारखाने का निर्माण-व्यय 190 करोड़ रुपया है। इसके निर्माण हेतु आवश्यक मशीनरी आयात करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सौ करोड़ रुपये का ऋण दिया है। इसमें 5 लाख टन यूरिया प्रति-वर्ष उत्पन्न की जायेगी। इस प्रकार यह एक विशाल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक खाद का कारखाना है।

इस कारखाने का निर्माण-कार्य 1976 में प्रारम्भ हो गया था और सितम्बर-अक्तूबर, 1979 में इसमें उत्पादन-कार्य शुरू हो जाना चाहिए था। खेद का विषय है कि इसके उत्पादन-कार्य में एक वर्ष से अधिक समय का विलम्ब होने जा रहा है, परन्तु उत्पादन प्रारंभ होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले घोषणा की गई कि कारखाना मई, 1980 में प्रारम्भ हो जायेगा। फिर कहा गया कि जुलाई-अगस्त, 1980 में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। परन्तु अभी तक सभी कुछ अनुमान पर ही चल रहा है। विदित हुआ है कि गत जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षण के आधार पर कारखाने को चालू किया गया था, परन्तु किसी हिस्से में आग लग जाने के कारण उसे बन्द कर देना पड़ा। परीक्षण में ही कुछ आवश्यक उपकरण जल जाने से कई लाख रुपये का नुक्सान हो गया है।

खाद के कारखाने में उत्पादन-कार्य प्रारम्भ होने से प्रति दिन लाखों रुपये का सीधा नुक्सान हो रहा है। इतनी बड़ी पूंजी लगा कर हज़ारों कर्मचारी कार्यरत हैं, परन्तु उत्पादन शून्य है। देश में वैसे भी रासायनिक खादों का अभाव है। इस वर्ष विदेशों से लगभग 2.3 मिलियन टन यूरिया का आयात करना पड़ेगा। माननीय उर्वरक मंत्री जी इस ओर पूरा प्रयास करें और कारखाने को चालू करने के लिए आवश्यक इनपुट फ़ैक्टर्ज़ की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करायें।

उर्वरक कारखाने के निर्माण हेतु वहां के किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था और उन्हें आश्वासन दिया गया कि भूमि देने वाले किसानों को कारखाने में काम दिया जायेगा, परन्तु अनेकों किसान इधर-उधर भटक रहे हैं। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि जिन किसानों की रोज़ी-रोटी का साधन छीन लिया गया है, उनके परिवार के लोगों को जीवन-यापन की सुविधा अवश्य प्रदान करे। माननीय मंत्री जी इसकी

जांच करा कर ऐसे लोगों को काम की सुविधा आवश्यक प्रदान करायें । निहित स्वार्थी लोगों को अन्यायपूर्ण ढंग से स्वार्थपूर्ति का अवसर नहीं मिलना चाहिए । किसी प्रकार की भेदभाव की नीति न अपनाई जाए, अन्यथा भुक्तभोगियों का असंतोष किसी भी समय भड़क सकता है ।

अन्त में मैं सम्बन्धित कारखाने में उत्पन्न अव्यवस्था की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा । यह आरोपित किया जा रहा है कि वहां के स्टोर से लाखों रुपये मूल्य के सामान चोरी चले गए हैं इस बात को ले कर कर्मचारियों में बड़ा असंतोष व्याप्त है । उन्होंने सुरक्षा अधिकारी एवं स्टोर अधीक्षक के निलम्बन की मांग की है । अपनी मांगों को ले कर कर्मचारी हड़ताल भी कर चुके हैं । अतः मेरा आग्रह है कि कारखाने के कार्यकलापों पर आवश्यक निगरानी रखी जाए एवं इंगित अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं की जांच कर उपयुक्त कार्यवाही की जाये ।

(iii) SUPPLY OF MORE RAILWAY WAGONS TO GUJARAT

SHRI DIGVIJAY SINH (Surendranagar): About 2,400 railway wagons per month have been allocated to the State of Gujarat, but the actual fulfiment has been only about 33 per cent, causing great hardship. Immediate remedial measures are sought for providing adequate wagons within one month, even if importation is necessary to overcome this critical situation.

(iv) PROGRAMME UNDERTAKEN BY SHIMILIPAL FOREST DEVELOPMENT CORPORATION IN MAYURBHANJ, ORISSA

SHRI MANMOHAN TUDU (Mayurbhanj) Mr. Speaker, Sir, in the district of Mayurbhanj, Orissa, Shimilipal Forest is predominantly inhabited by Adivasis belonging to the different tribes. Now, the programme undertaken by Shimilipal Forest Development Corporation is being implemented in this area. This is a Central Government programme that is being implemented by the State Government.

In the name of the implementation of programme, the possession of the entire area has been done and the demarcating lines have been drawn. In this process, 50 thousand tribal people are being evicted from their respective residential houses and they are being deprived of the fruits of their labour and forest products on which they were traditionally depending for their livelihood. The programme, therefore, is being resisted by the inhabitants of that locality. The inhabitants of that area are now facing starvation and denied access to the forest. Even Atheradeuli Cave temple which is a centre of religious worship of Adivasis which is a legendary place and called the capital of King Virat in Mahabharat has been taken over by the Shimilipal Forest Development Corporation and Adivasis and others are denied their fundamental rights to worship at this place.

I, therefore, urge upon the Government of India to examine the matter and take appropriate steps not to disturb the local inhabitants from their residential areas and their accessibility for the forest products. The religious Atheradeuli Cave be kept open for religious worship as has been the practice for ages. The Shimilipal Forest Development Corporation should be directed accordingly to operate in areas outside the village boundary. This issue involves the life and death of 50,000 people of my constituency. There will be serious breakdown of law and order in this area and the uncontrolled wrath of tribals may descend upon